

केरल में अवसंरचना को प्रोत्साहन

प्रलमिस् के लयि:

[राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन \(NIP\)](#), [प्रधानमंत्री गतशक्तियोजना](#), विश्व बैंक द्वारा भारत की शहरी अवसंरचना आवश्यकताओं का वतितपोषण, [राष्ट्रीय अवसंरचना वतितपोषण और वकिस बैंक \(NBFID\)](#), [वकिसति भारत](#), [अमृत काल](#), [मेक इन इंडिया](#)

मेन्स के लयि:

भारत का बुनयिदी ढाँचा क्षेत्र- महत्त्व, चुनौतयिँ और संबधति पहल

[स्रोत: द हद्वि](#)

चर्चा में क्यौं?

हाल ही में [प्रधानमंत्री \(Prime Minister- PM\)](#) ने कोच्चि केरल में तीन परयोजनाओं का उदघाटन कयि जसिमेंकोचीन शपियार्ड लमिटिड (CSL) में न्यू डराई डॉक (NDD), CSL की अंतर्राष्ट्रीय जहाज़ मरम्मत सुवधि (International Ship Repair Facility- ISRF) एवं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लमिटिड (IOCL) का LPG आयात टर्मिनल शामिल हैं।

- ये प्रमुख अवसंरचना परयोजनाएँ भारत के बंदरगाहों, पोत परिवहन और जलमार्ग क्षेत्र को बदलने तथा इसमें क्षमता सृजन एवं आत्मनिर्भरता के लिये प्रधानमंत्री के वज़िन के अनुरूप हैं।

केरल में उदघाटन की गई तीन वभिन्नि परयोजनाएँ क्या हैं?

- न्यू डराई डॉक:**
 - 310 मीटर की लंबाई के साथ न्यू डराई डॉक (NDD) अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाया गया है।
 - यह राष्ट्रीय गौरव इंजीनियरिंग का चमत्कार है जो INS वकिरांत अथवा अन्य बड़े जहाज़ों के वसिथापन से दोगुने वमिन वाहक को संभालने में सकषम है।
 - भारत के इंजीनियरिंग कौशल और परयोजना प्रबंधन क्षमताओं को दर्शाने वाली एक प्रमुख परयोजना NDD इस क्षेत्र के सबसे बड़े समुद्री अवसंरचना में से एक है।
 - इसमें दक्षता, सुरक्षा और पर्यावरणीय संधारणीयता सुनश्चिति करने के लिये नवीनतम तकनीक तथा नवाचारों को शामिल कयि गया है।
- अंतर्राष्ट्रीय जहाज़ मरम्मत सुवधि:**
 - अंतर्राष्ट्रीय जहाज़ मरम्मत सुवधि (ISRF) भारत का पहला पूर्ण रूप से वकिसति शुद्ध जहाज़ मरम्मत पारसिथितिकी तंत्र है जो जहाज़ मरम्मत उद्योग की क्षमता में 25% की वृद्धि करेगा।
 - ₹970 करोड़ के नविश पर नरिमति यह आपातकालीन स्थिति के दौरान भारत के नौसेना और तटरक्षक जहाज़ों के लिये त्वरति टर्नअराउंड (जहाज़ पर से माल उतारने व लादने की करयि) प्रदान करेगा।
 - ISRF, CSL की वर्तमान जहाज़ मरम्मत क्षमताओं का आधुनिकीकरण तथा वसितार करेगा एवं इसे एक वैश्विक जहाज़ मरम्मत केंद्र के रूप में परिवर्तित करेगा।
- IOCL के लिये LPG आयात टर्मिनल:**
 - IOCL के लिये एक LPG आयात टर्मिनल का भी कोच्चि में उदघाटन कयि गया, जसिमें 3.5 कमी. लंबी क्रॉस कंट्री पाइपलाइन के माध्यम से मल्टी-यूज़र लकिवडि टर्मिनल जेट्टी से जुड़े अत्याधुनिक अवसंरचना के साथ काम कयि गया है।
 - टर्मिनल का लक्ष्य 1.2 मिलियन मीटरकि टन प्रतिवर्ष (MMTPA) का कारोबार प्राप्त करना है। यह सड़क व पाइपलाइन हस्तांतरण के माध्यम से LPG वतिरण सुनश्चिति करेगा, जसिसे केरल और तमलिनाडु में बॉटलिंग संयंत्रों को प्रत्यक्ष लाभ होगा।
 - यह LPG की नरितर आपूर्ति सुनश्चिति करके भारत के ऊर्जा अवसंरचना को भी महत्त्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगा, जसिसे क्षेत्र और उसके आसपास के लाखों परिवारों एवं व्यवसायों को लाभ होगा।
 - यह परयोजना सभी के लिये सुलभ और सस्ती ऊर्जा सुनश्चिति करने की दशि में भारत के प्रयासों को और मज़बूत करेगी।

इन परयोजनाओं का महत्त्व क्या है?

- **समुद्री विकास हेतु रणनीतिक दृष्टिकोण:**
 - प्रधानमंत्री ने '**सबका साथ, सबका विकास**' दृष्टिकोण से जुड़ी परियोजनाओं द्वारा स्थापित वैश्विक बेंचमार्क पर जोर दिया।
 - **मैरीटाइम अमृत काल वजिन- 2047** कोच्चि को एक प्रमुख **समुद्री क्लस्टर और ग्रीन शिप हेतु एक वैश्विक केंद्र** के रूप में विकसित करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की रूपरेखा तैयार करता है, जो उत्कृष्टता एवं नवाचार के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- **समुद्री क्षेत्र में नविश और रोजगार:**
 - इस पहल का लक्ष्य 45,000 करोड़ रुपए का महत्वपूर्ण नविश प्राप्त कर समुद्री क्षेत्र में 50,000 से अधिक लोगों के लिये रोजगार सृजन करना है।
 - ये प्रयास भारत के टन भार को बढ़ाने, **आत्मनिर्भर** बनने और विदेशी जहाजों पर भारत की निर्भरता को कम करने पर केंद्रित हैं।
- **कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL) की भूमिका:**
 - CSL, जसै **नॉर्वे में स्वायत्त इलेक्ट्रिक नौकाएँ/जहाज (Barges) उपलब्ध कराने** के लिये विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है, एक प्रमुख समुद्री/मैरीटाइम अग्रणी के रूप में भारत के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
 - **अगली पीढ़ी के हरित प्रौद्योगिकी (Next-Generation Green Technology) जहाजों** सहित शिपयार्ड का प्रभावशाली उत्पाद पोर्टफोलियो इसे भारत के समुद्री उद्योग में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में स्थापित करता है।
- **राष्ट्रीय गौरव और पर्यावरणीय प्रभाव:**
 - कोच्चि में राष्ट्रीय गौरव की प्रतीक परियोजनाएँ भारत की अभियांत्रिकी शक्ति को प्रदर्शित करती हैं। इनसे पर्यावरणीय दायित्व पर जोर देते हुए महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक बचत और CO2 उत्सर्जन को कम करने की उम्मीद की जाती है।
- **वैश्विक दृष्टिकोण के साथ संरेखण:**
 - **मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (MEEEC)** के संबंध में **भारत की G20 अध्यक्षता** के दौरान किये गए समझौतों पर प्रकाश डालते हुए, PM ने रेखांकित किया कि MEEEC भारत की तटीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देकर विकसित भारत के निर्माण को और भी मजबूत करेगा।
- **समुद्री बुनियादी ढाँचे के लिये भविष्य की योजनाएँ:**
 - बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय इन परियोजनाओं के आधार पर भविष्य की योजनाओं की रूपरेखा तैयार करता है, जिसमें शामिल हैं:
 - जहाज निर्माण एवं मरम्मत में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना।
 - रणनीतिक स्थानों पर जहाज मरम्मत समूहों का निर्माण।
 - जहाज मरम्मत क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिये व्यापार शर्तों में छूट।
 - वाडनार में जहाज मरम्मत सुविधा के लिये चर्चा चल रही है।

प्रमुख एवं छोटे बंदरगाह:

- **भारत के प्रमुख बंदरगाह:**
 - देश में **12 प्रमुख बंदरगाह और 200 गैर-प्रमुख बंदरगाह (छोटे बंदरगाह)** हैं।
 - प्रमुख बंदरगाहों में दीनदयाल (पूर्ववर्ती कांडला), मुंबई, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, मरमुगाओ, न्यू मैंगलोर, कोचीन, चेन्नई, कामराजर (पहले एन्नोर), वी. ओ. चिदिबरनार, वशिखापत्तनम, पारादीप और कोलकाता (हल्दिया सहित) शामिल हैं।
- **प्रमुख बंदरगाह बनाम छोटे बंदरगाह:**
 - भारत में बंदरगाहों को भारतीय बंदरगाह अधिनियम, 1908 के तहत परिभाषित केंद्र और राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र के अनुसार प्रमुख एवं छोटे बंदरगाहों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
 - सभी **12 बंदरगाह, प्रमुख बंदरगाह ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के तहत शासित हैं और केंद्र सरकार के स्वामित्व और प्रबंधन में हैं।**
 - सभी छोटे बंदरगाह, भारतीय बंदरगाह अधिनियम, 1908 के तहत शासित हैं और राज्य सरकारों के स्वामित्व तथा प्रबंधन में हैं।
- **हाल में हुए विकास:**
 - भारतीय बंदरगाहों ने पिछले 10 वर्षों में दोहरे अंक की वार्षिक वृद्धि हासिल की है।
 - जब बदलाव के समय की बात आती है तो भारत कई विकसित देशों से आगे निकल गया है।
 - भारतीय नाविकों से संबंधित कानूनों में समय पर बदलाव से उनकी संख्या में **140% की वृद्धि हुई है।**

Roadblocks in key sectors



HIGHWAYS

- Delays in land acquisition; lenders stop lending midway
- Tendering of projects to low-traffic entity
- Unclear exit policy for road developer; NHAI is a developer as well as the regulator which causes a conflict of interest in case of arbitration so there is a need for a clear distinction of roles for NHAI

PORTS

- Multiple changes in tariffs setup by the Tariff Authority for Major Ports make it difficult to evaluate the cost of projects
- Delays in tariff fixation

AIRPORTS

- Lack of consistency in tariff methodology and concession tariff framework
- Switching from single till tariff method to hybrid till creates difficulty in assessing the cost of projects
- Delays in the passage of tariff orders cause problems in the timely execution of projects

WIND

- Inconsistent policy at Central and State govt level
- Accelerated depreciation leads to non-viability
- State regulators do not honour renewable purchase obligation

TELECOM

- Lack of predictability
- Inconsistent policy and regulatory framework; govt refuses to honour PPAs signed earlier
- Aggressive bidding to some extent

POWER

- Coal block deallocation causing execution delays and losses to project developers
- New auction-based coal linkage approved by government in 2017, uncertainty remains regarding the validity of old contracts
- Inconsistency in the interpretation of PPA
- Inconsistency in Central & State regulation, for instance, the Central electricity Act allows open access, but State governments do not adhere to it causing the problem in execution
- Unstable financial health of State utility causes a delay in the payment cycle

GREENFIELD PROJECTS

- Land acquisition delay
- Nature of developers have been contractors which leads to low-cost bidding making the project unviable
- Bank loans are given out for 10/15/18 years but the interest reset clause poses a high risk on overall investment return evaluation, sometimes 8% interest rates are increased up to 14-15% rendering the project unviable

BROWNFIELD PROJECTS

- Government questions the validity of existing projects (eg, with rates of solar energy slashing, will the contracts entered on higher tariffs remain valid or not?)
- There is a strong need for the ability to have more credible infrastructure developers and partners

UNIFIED LOGISTICS INTERFACE PLATFORM (ULIP) IS DESIGNED TO ENHANCE EFFICIENCY AND REDUCE THE COST OF LOGISTICS BY CREATING A TRANSPARENT, ONE-WINDOW PLATFORM

बुनियादी ढाँचा क्षेत्र को मज़बूत करने हेतु क्या उपाय किये जा सकते हैं?

- नीति/नियामक ढाँचे में नरितरता सुनिश्चित करना:
 - नविदा प्रक्रिया में एक बेहतर नियामक वातावरण और नरितरता की आवश्यकता है। वभिन्न सरकारी वभागों में नरितरता और नीतिगत सामंजस्य की कमी को प्राथमिकता से संबोधित किया जाना चाहिये।
 - तनावग्रस्त परसंपत्तियों की समस्या से निपटने के लिये सरकार और RBI के मध्य एक समग्र दृष्टिकोण होना चाहिये।
 - गैर-नविदा संपत्तियों, PSUs के पुनरुद्धार के लिये सभी क्षेत्रों में एक समरूप नीति का निर्माण करने की आवश्यकता है।
- उचित उपयोगकर्ता शुल्क:
 - यह अवसंरचना वतिपोषण, अवसंरचना सेवा प्रदाताओं की वतितीय व्यवहार्यता और पर्यावरण एवं संसाधन उपयोग संवहनीयता को बढ़ाने के लिये यह आवश्यक है।
 - उपयोगकर्ता शुल्क महत्त्वपूर्ण हैं क्योंकि देश भर के कई क्षेत्रों में आंशिक रूप सेशून्य या बहुत कम उपयोगकर्ता शुल्क के कारण कीमती संसाधनों (जैसे- भूजल) का अत्यधिक उपयोग एवं अपव्यय होता है।
 - उचित उपयोगकर्ता मूल्यों से प्रेरित पर्यावरणीय संवहनीयता एवं संसाधन उपयोगदक्षता के अलावा इस नीति प्राथमिकता में अपार संसाधन सृजन क्षमता भी है।
- स्वायत्त अवसंरचना के वनियमन:
 - जैसे-जैसे भारत और वशिव नजी भागीदारी के लिये अधिक क्षेत्रों को खोलेंगे, नजी क्षेत्र अनवार्य रूप से स्वायत्त अवसंरचना के वनियमन की मांग करेगा।
 - वशिव में रुझान बहु-क्षेत्रीय नयामकों की ओर है क्योंकि बुनियादी ढाँचा क्षेत्रों में नयामक भूमिका आम है और ऐसे संस्थान नयामक

- परसिंपत्तपुनरचक्रण (AR) और BAM:

- भारत के पास बुनियादी ढाँचा क्षेत्रों में ब्राउनफील्ड परसिपततियों का एक बड़ा भंडार है।

- भारतीय पेंशन फंड जैसे घरेलू स्रोत, जो नषिक्रयि पड़े हैं, यदि कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाए तो इस क्षेत्र को बड़ा बढ़ावा मिल सकता है।
- भारत अवसंरचना के विकास को बढ़ावा देने के लिये घरेलू धन के कुशल उपयोग पर कनाडा, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों की प्रथाओं का अनुकरण कर सकता है।

- प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना
- राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन
- शहरी अवसंरचना विकास नधि
- राष्ट्रीय लाजसिटिक्स नीति
- डेडकिटेड फरेट कॉरिडोर
- सागरमाला परियोजना

?????????:

1. यह नीति आयोग का एक अंग है।
2. वर्तमान में इसके पास 4,00,000 करोड़ का कोष है।

(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 2. भारत में "सार्वजनिक रूप से महत्त्वपूर्ण बुनियादी अवसंरचना" शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है (वर्ष 2020)

- (A) डिजिटल सुरक्षा बुनियादी अवसंरचना
(B) खाद्य सुरक्षा बुनियादी अवसंरचना
(C) स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा हेतु बुनियादी अवसंरचना
(D) दूरसंचार और परिवहन बुनियादी अवसंरचना

?????

प्रश्न. “अधिक तीव्र और समावेशी आर्थिक विकास के लिये बुनियादी अवसंरचना में निवेश आवश्यक है।” भारत के अनुभव के आलोक में चर्चा कीजिये। (वर्ष 2021)

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/current-affairs-news-analysis-editorials/news-analysis/19-01-2024/print>

